INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 12 | ISSUE - 1 | FEBRUARY - 2022

राजनीति में युवाओं की भागीदारी का अध्ययन

विजय कुमार साकेत[1] , डॉ. गायत्री मिश्रा[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान , शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान , शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

आधुनिक काल में टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाषचंद्र बोस जैसे युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलनों को सफल बनाने एवं उनके नेतृत्व में भारत को आजादी दिलाने में कई युवा नेताओं का भी योगदान रहा है। यदि आजादी से लेकर अब तक के सात दशकीय समकालीन भारत के इतिहास की बात की जाए तो इस काल में भी हुए कई आंदोलनों और परिवतनों का नेतृत्व युवाओं ने ही किया है। भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने (हरित क्रांति) से लेकर परमाणु शक्ति संपन्न बनाने तक का जिम्मा युवा कंधों ने उठाया। कंप्यूटर क्रांति व नई आर्थिक नीति भी युवा मस्तिष्क की ही उपज थी।

मुख्य शब्द – राजनीति, युवा, भागीदारी एवं आंदोलन।

प्रस्तावना –

यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पच्चीस वर्ष तक की आयु वाले लोग कुल जनसंख्या का पचास फीसद हैं, वहीं पैंतीस वर्ष तक वाले कुल जनसंख्या का पैंसठ फीसद हैं। यही कारण है कि इसे दुनिया भर में उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है और इक्कीसवीं सदी की महाशक्ति होने की भविष्यवाणी की जा रही है। युवा आबादी ही देश की तरक्की को रफ्तार प्रदान कर सकती है। जैसा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप मे अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाए जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं।

यह बात शत–प्रतिशत सत्य है कि बिना खनिज संसाधन के भी किसी देश का विकास हो सकता है, लेकिन बिना मानव संसाधन के देश के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान का ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की इबारत लिखी और आज दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए ता बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा जैसे राज्य संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल, कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे हैं।

युवाओं के दिग्भ्रमित होने और गलत रास्ते पर जाने का एक कारण लोग बेरोजगारी को मानते हैं। लेकिन युवाओं को अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का एकमात्र जरिया है। भारतीय समाज में यह आमधारणा है कि सरकारी नौकरी ही जीवन की सफलता का पैमाना है। समाज के लोगों को इस धारणा को बदलना होगा। उदारीकरण एवं सूचना क्रांति के आधुनिक युग में रोजगार एवं स्वरोजगार

की संभावनाओं की कमी नहीं है। इसका उदाहरण अमेरिका और यूरोपीय देशों से ले सकते हैं जहां युवा इन संभावनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। भारत में भी गुजरात का उदाहरण ले सकते हैं जहां लोगों ने उद्यमशीलता के बूते स्वयं को और देश के अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सक्षम बनाया है।

विश्लेषण –

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बावजूद यहां राजनीति में युवाओं की भागीदारी बेहद कम है। अक्सर देखा गया है कि राजनीति को लेकर युवाओं में नकारात्मकता का भाव होता है, इसलिए वे राजनीति में नहीं आना चाहते। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि जब तक वे राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे, तब तक राजनीति से नकारात्मकता दूर नहीं होगी। भारतीय संविधान ने अठारह साल से अधिक उम्र के युवाओं को मतदान का अधिकार दिया हुआ है। ऐसे में युवाओं की भूमिका काफी अहम हो जाती है।

इसके अलावा युवाओं को बेहतर मानव संसाधन में बदलने के लिए शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार की जरूरत है। देश के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अभी भी परंपरागत तरीके से ही पढ़ाई हो रही है। इस कारण हमारे विश्वविद्यालय वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष अभी भी यह है कि प्राप्तांकों को बहुत महत्त्व दिया जाता है जिसकी वजह से बच्चों में रटने की प्रवृत्ति हो जाती है और उनमें मौलिकता एवं रचनात्मकता का विकास नहीं हो पाता है। यही कारण है कि हम नवाचार एवं नवोन्मेष में पिछड़े हुए हैं। इसके लिए हमें शिक्षा के प्राथमिक एवं उच्च दोनों ही स्तर पर सुधार के प्रयास करने होंगे।

जहां तक बात है शोध और अनुसंधान के क्षेत्र की, तो इसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि देश में प्रतिभाओं की कमी है। देश के ही युवा जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों में जाते हैं तो वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं और नोबेल जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी पाते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो भारत के युवाओं का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन प्रतिभा–पलायन की वजह से हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि युवाओं की तरक्की से ही देश होगी। जिस दिन राजनीति से लेकर प्रशासन तक, समाज से लेकर विज्ञान तक, खेल से लेकर कारोबार तक युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उस दिन देश का भविष्य उतना ही उज्ज्वल होगा।

चुनाव के समय हमें अपनी युवा शक्ति की याद आती है। छात्रो और युवाओं की राजनीति में भागीदारी का सवाल पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है । विशेष कर जब जब देश में चुनाव की रणभेरी बजी है या जब कभी इस युवा शक्ति ने किसी बडे आंदोलन को जन्म दिया या फिर किसी घटना विशेष पर अपने तीखे आक्रोश से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने मे सफल हुए , यह सवाल बहस का विषय बना । इस बार का चुनाव युवाओं की भागीदारी के लिए भी जाना जायेगा। यह दीगर बात है कि चंद दिनों के बाद इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत महसूस नही होगी। युवाओं के बीच राजनीति किस सीमा तक होनी चाहिये यह अभी तक तय नही हो सका है। क्या यह कम आश्चर्यजनक नही कि जहां दुनिया के दूसरे देशों में यह भूमिका स्पष्ट है वहीं दुनिया के सबसे बडे इस लोकतांत्रिक देश मे जहां युवा निर्णायक भूमिका मे हैं तस्वीर अभी तक साफ नही हो पायी है।

देश के अधिकांश विश्वविधालयों व कालेजों में छात्रसंघों के चुनाव होते हैं। रंगीन पोस्टर व बैनरों से कुछ दिन के लिए पूरा शहर पट सा जाता है । अब तो परिसर के अंदर कम बाहर शोर अधिक सुनाई देता है। हिंसात्मक घटनाओं से लेकर उम्मीदवार के अपहरण व हत्या तक की वारदातों को देख सुन अब किसी को हैरत नही होती। विजयी उम्मीदवारों के जुलूस पूरे शहर को मंत्रमुग्ध कर आकर्षण तथा चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन इसके बाद यह छात्र नेता और छात्रसंघ क्या कर रहे हैं इसका पता किसी को नही लगता । इतना अवश्य है कि समय समय पर दुकानों को लूट्ने, होट्लों में बिल अदा न करने, स्थानीय ठेकों को हथियाने के प्र्यास में मारपीट करने के कारण छात्र शक्ति चर्चा का विषय बंनती है। या फिर चुनाव के समय हमें अपनी युवा शक्ति की याद आती है ।

वर्तमान से उठते इन सवालों पर जरा गहराई से विचार करें तो पता चलता है कि नाउम्मीदी के बादल इतने घने भी नही हैं। अतीत गवाह है कि महात्मा गांधी, सुभाष च्न्द्र बोस और जय प्र्काश नरायण के आहवान पर छात्र संगठन जो कर गुजरे वह आज इतिहास बन गया है । स्वतंत्रता पूव की इस युवा राजनीति का सुनहला इतिहास रहा है। 1905 में कलकत्ता विश्वविधालय के दीझांत समारोह में लार्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन

की बात बडे हल्के ढंग से कही थी लेकिन छात्रों को समझते देर न लगी । जल्द ही पूरे राज्य मे इसके विरूद आंदोलन शुरू हुए। एकबारगी अंग्रेज सरकार हैरत मे पड गई । बंगाल से उपजी यह चेतना जल्द ही दूसारे राज्यों में भी फैल गयी । 1920 मे नागपुर में अखिल भारतीय कालेज विधार्थी सम्मेलन हुआ और नेहरू के प्यासों से छात्र संगठनों को सही अर्थो मे अखिल भारतीय स्वरूप मिला । इसके बाद वैचारिक मतभेदों को लेकर संगठनों में टूट फूट होती रही ।

कुछ वर्षों तक कुछ भी सार्थक न हो सका । सत्तर के दशक में दो महत्वपूर्ण घट्नाएं अवश्य युवा राजनीति के क्षितिज मे उभरीं । पहला 1974 मे ज़े.पी. आंदोलन जो व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर शुरू हुआ। दूसरा असम छात्रों का आंदोलन जिसकी सुखद परिणति हुई तथा युवा छात्र सत्ता में भागीदार बने । बाकी याद करने लायक कुछ दिखाई नही देता ।

मंडल आयोग को लेकर युवा आक्रोश जिस रूप मे प्रकट हुआ इससे तो एक बारगी पूरा देश हतप्रद रह गया। इधर कुछ वर्षों से छात्र राजनीति मे राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप इस सीमा तक बढा है कि इसमे वे छात्र ही उभर सकते हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुडे होने और सभी चुनावी पैतरों का इस्तेमाल कर सकते हों। दलगत राजनीति के साथ ही जातीय, क्षेत्रीय व साम्प्र्दायिक समीकरणों को भी बल मिला है। बिहार व उत्तर प्रदेश के अधिकांश कालेजों में चुनाव जातीय समीकरणों के आधार पर लडे जा रहे हैं। इस तरह स्थिति बद से बदतर हो रही है। जिस तरह से परिसर मे दलीय राजनीति अपना रंग दिखाने लगी है इससे यह बात साफ हो चली है अब निर्णय लेना होगा कि परिसर की राजनीति संसद या विधानसभाओं को मद्देनजर चलाई जानी चाहिये या सिर्फ छात्रों द्वारा परिसर के लिऐ क्योंकि इन दो अलग अलग उदेश्यों के लिऐ भिन्न राजनीतिक चरित्र का होना जरूरी है।

ऐसा नही कि छात्र व युवा राजनीति में संभावनाओं का आकाश बहुत सीमित है ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होने आगे चल कर राष्ट्रीय राजनीति मे महत्वपूर्ण योगदान दिया लेकिन छात्र जीवन मे उन्हे किसी राजनैतिक दल की छ्तरी की आवश्यकता महसूस नही हुई। डा. जाकिर हुसैन अलीगढ विश्वविधालय की ही उपज थे। इनके अलावा डा. मौलाना आजाद, शेख अब्दुल्ला , फखरूदीन अली अहमद भी अपने छात्र जीवन म यहां के छात्र संगठन से जुडे रहे। इलाहाबाद विश्वविधालय के छात्र संघ ने भी कई राजनेता देश को दिये । हेमवती नंदन बहुगुणा, वी.पी.सिंह , चंदशेखर, नुरूल हसन, जानेश्वर मिश्र, मोहन सिंह आदि ने राष्ट्रीय राजनीति मे अपनी पुख्ता पहचान बनाई। लखनउ विश्वविधालय और दिल्लो विश्वविधालय ने तो कई नेताओं को संसद पहुंचाया ।

निष्कर्ष –

युवा राजनीति बुनियादी उद्देश्यों से भटक गई है। आज के संगठन जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा द्लगत राजनीति के शिकार होकर रह गये हैं। यही नही, राजनीतिक दलों द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है ।

सोचा जाना चाहिए कि यह कैसी राजनीति है जो लोहिया व जय प्रकाश का नारा देकर आगजनी व लूटपाट को बढावा दे रही है। इसी राजानीति का ही परिणाम है कि छात्र आंदोलन आम छात्र से कटने लगा है। ' आई हेट पालिटिक्स ' कहने वाले वर्ग का जन्म इसी राजनीति के गर्भ से हुआ है । इधर कुछ समय से युवा वर्ग मे सुखद बदलाव के संकेत दिखाई देने लगे हैं । वह राजनीति को समझ्ने की कोशिश करने लगा है और उसमे भागीदारी भी । वह आवाज उठाने लगा है। अपने वोट के महत्व को वह समझने लगा है । इसमें संदेह नही कि यह आम चुनाव भी युवाओं की सक्रियता के लिए जाना जायेगा और बहुत हद तक युवाओं की भागीदारी चुनाव के परिणाम को तय करेगी । स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी भी है ।

संदर्भ –

स. क्र.	लेखक	पुस्तक विवरण	प्रकाशन / वर्ष
1	2	3	4
1	ओमन टी.के.	पालिटिकल लीडरशिप इल रुरल इण्डियन इमेज एण्ड रियलिटि एशियन सर्वे वाल्यूम 9 (7)	1969

2	अग्निहोत्री गुरु राम प्यारे	रीवा राज्य का इतिहास म.प्र. शासन साहित्य परिषद् भोपाल	1972
3	वशु दुर्गादास	भारत का संविधान एक परिचय, प्रकाशन बाधवा एण्ड कम्पनी नई दिल्ली	2003
4	भार्गव अरुणा	ग्रामीण नगरीय संरचना, आफसेट प्रिंटर्श जयपुर	1996
5	बघेल डी.एस.	सामाजिक अनुसंधान–साहित्य भवन पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्श (प्रा.) लिमिटेड आगरा	2000
6	बशु डी.डी.	कमेस्ट्री आनंद कान्सटीट्शनल ऑफ इण्डिया आठव संस्करण	2008
7	बलवंत बाबूलाल	बी.एड. सम्पूर्ण अध्ययन संस्करण	2005–06
8	बेयर एक्ट	भारतीय संविधान कानून प्रकाशन	
9	बसु अमृता	भारत का संविधान इलाहाबाद ला एजेंसी ग्यारहवां संस्करण	2004
10	चतुर्वेर्दी मुरलीधर	भारत का संविधान इलाहाबाद ला एजेन्सी ग्यारहवां संस्करण	2004
11	चटोपाध्याय प्रतिभा	श्राधाकृष्णन सेन्चुरी वाल्यूम न्यू दिल्ली आक्सपोर्ट युनिवर्सिटी लन्दन	1989
12	दीक्षित देव ब्रत	भारत में पंचायती राज का क्रमिक विकास भाग–3 ग्राम विकास प्रकाश लखनऊ	
13	बोस प्रदीप कुमार	रिसर्च मेथडालाजी न्यू डेल्ही आई.सी.एस.आर.	1995
14	द्विवेदी हरिहर निवास	मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–ला जर्नल पब्लिकेशन ग्वालियर	1994
15	चवन शेषराव	गाँधी और अम्बेडकर सेवियर ऑफ अनटचे विल्टी वाल्यून–1 भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली	2011
16	इंजीनियर आनन्द मिश्रा	21वीं शदी में शिक्षा चुनौतियों में शिक्षा के महत्व व उपाय म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग	2010
17	दीपा तिवारी	हिन्दी भाषा एवं नैतिक मूल्य म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल प्रथम संस्करण	2016
18	कश्यप सुभाष	कान्सटीट्शनल ला ऑफ इण्डिया	
19	ग्रोवर वी.एल.	आधुनिक भारत का इतिहास एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली।	2006
20	जैन एम.पी.	इण्डिया कस्टीट्यूशन ला बाधवा प्रकाशन बाम्बे।	2001
21	कटोच ए.एस.	एज्युकेशन फार वैल्यु जैन ब्रदर्श नई दिल्ली	2006
22	कुमार सुरेन्द्र	हयूमन राइट एज्युकेशन आकांक्षा पर पब्लिसर नई दिल्ली	2012
23	कुमार विजय	भारतीय सामाजिक विकास में शिक्षा का अधिकार के क्रियान्वयन वाल्यूम–1 अकांक्षा प्रकाशन नई दिल्ली	2012

विजय कुमार साकेत
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान , शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान , शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)